बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 168 ● नई दिल्ली ● वीरवार 03 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

अनुसूचित जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार मामले में एनएचआरसी की कार्रवाई

भुवनेश्वर । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बुधवार को ओडिशा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। दरअसल गंजाम जिले में दो अनुसूचित जाति के लोगों को अवैध पशु तस्करी के संदेह में बुरी तरह पीटा गया था, उन्हें घास खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया था। मानवाधिकार आयोग ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ितों के मोबाइल फोन छीन लिए और जबरन उनके सिर भी मुंडवा दिए। ये अत्याचार कथित तौर पर एक अन्य समुदाय के लोगों द्वारा किए गए। एनएचआरसी ने अपने बयान में कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट की बातें सच है, तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है।

रेखा गुप्ता ने शीश महल का किया अनावरण, सीएम आवास पर सवालों के बीच अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज

नई दिल्ली । दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल डीडीए शालीमार बाग में पुनर्निर्मित संरचनाओं और शीश महल का अनावरण किया. इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था. दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था और ये एक शीश महल है जो जनता को समर्पित कर, उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है. ये फर्क है, पहले की सरकारों में और इस सरकार की कार्य प्रणाली में. मैं तो यही कहूंगी कि जनता का शीश महल आबाद रहे और जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया उनको तो कानून ही देखेगा. रेखा गुप्ता का इशारा अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के समय बने नए मुख्यमंत्री आवास की तरफ था. बीजेपी ने इस आवास में मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र करते हुए इसे शीश महल बताया था. विधानसभा चुनाव के समय इस आवास को बड़ा मुद्दा बनाया. रेखा गुप्ता ने ऐसे समय में शीश महल का जिक्र किया है, जब आम आदमी पार्टी (आप) सीएम के नए आवास को लेकर हमलावर है. आप ने 2

जुलाई को एक्स पर लिखा, एक तरफ दिल्लीवाले तमाम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं. सरकार की बिना सिर पैर वाली नीतियों से परेशान हैं. जनता अपने घर रोजगार को बचाने के लिए परेशान है. दिल्ली के निजी स्कूलों की बढ़ती फीस, बिजली कटौती, पानी की किल्लत, राजधानी में बढ़ते अपराध, महंगाई और बेरोजगारी से एक-एक दिल्लीवाला परेशान है. आप ने कहा, ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता अपने 'मायामहल' में करोड़ों रुपए लगवाकर Renovation करवा रही है. इस Renovation में उनके 'मायामहल' में लाखों के एसी, झूमर, टीवी और लाइट लगाई जायेंगी. इसमें करोड़ों रुपये का खर्च होगा. सीएम रेखा गुप्ता को राज निवास मार्ग स्थित बंगला नंबर 1 आवंटित किया गया है. जून 2024 में, एएसआई ने साइट पर संरक्षण कार्य का पहला चरण शुरू किया, जिसमें शालीमार बाग के शीश महल की संरचना को ठीक करना शामिल था. 17वीं सदी के शीश महल के जीर्णोद्धार कार्य किया गया है. केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि शालीमार बाग दिल्ली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका इतिहास बहुत समृद्ध है. शालीमार बाग का शीश महल 400 से अधिक वर्षों से दिल्ली के लिए गौरव का विषय रहा है. हालांकि, आजादी के बाद सत्ता में आने वाली पार्टियों ने, कुछ को छोड़कर, कभी भी इन ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण में रुचि नहीं दिखाई. एलजी वीके सक्सेना ने व्यक्तिगत रूप से इन ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार की पहल की. एएसआई और डीडीए ने इन स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए मिलकर काम किया.

संसद की सुरक्षा में सेंध के आरोपी नीलम-महेश को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली । संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर राहत प्रदान की। बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले निचली अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद आरोपियों ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देने से पहले कुछ शर्तें भी रखी हैं। न्यायाधीश ने उन्हें मीडिया को साक्षात्कार न देने और घटना से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट न करने का भी निर्देश दिया। मामला 2023 का है, जिस दिन संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी थी। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन डी दर्शक दीर्घा से नीचे सदन में कूद गए थे। उन्होंने जूते से स्मोक कैन निकालकर पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी की। लगभग उसी समय, दो अन्य आरोपियों अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद परिसर के बाहर रंगीन गैस छोड़ी और नारेबाजी की। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

बिना ट्रायल लागू नियम से पहले दिन पेट्रोल पंपों पर आई तकनीकी दिक्कतें, जनता ने उठाए सवाल

नई दिल्ली।राजधानी में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक जुलाई से तय उम्र सीमा पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने पहुंचे लोगों ने कैमरे और साउंड सिस्टम समेत अन्य तकनीकी खामियां नजर आने पर बिना ट्रायल लागू इस नियम पर सवाल भी उठाए। हालांकि 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुराने डीजल के 20 से 25 वाहनों को मंगलवार को जब्त भी किया गया। इस नियम से राज्यों के बॉर्डर पर स्थित राजधानी के पेट्रोल पंपों पर ईंधन बिक्री में गिरावट की बात भी सामने आई है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (डीपीडीए) के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने बताया कि राजधानी में 400 के करीब पेट्रोल पंप हैं। इनमें से कई पेट्रोल पंपों पर अभी साउंड नहीं लग पाया है। ऐसे में स्पीकर से अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित जो कैमरे लगाए गए हैं वे दिल्ली परिवहन विभाग के डेटाबेस से लिंक हैं। ओवरएज वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करते ही पेट्रोल पंप पर लगे स्पीकर पर अलार्म बजता है। साथ ही स्पीकर पर बताया जाता है कि वाहन उम्र पूरी कर चुका है। यह सूचना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी चली जाती है। स्पीकर नहीं लगा होने से कई पेट्रोल पंपों पर दिक्कत आई। निश्चल सिंघानिया ने बताया कि गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के पास दिल्ली सीमा में जो भी पेट्रोल पंप हैं। उनपर पेट्रोल व डीजल की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पुराने वाहन गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद से पेट्रोल व डीजल ले रहे हैं। हालांकि इस साल एक नवंबर से इन जिलों में भी पुराने वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लग जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उम्र पूरी कर चुके वाहन को यदि को पहली बार जब्त किया गया है तो उसे छुड़ाया जा सकता है लेकिन उसके लिए वाहन मालिक को जुर्माना भरने के साथ विभाग को शपथ पत्र देना होगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन स्क्रैप कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे वाहन जो पहली बार जब्त किए गए हैं उन्हें 21 दिन के भीतर वाहन मालिक बाइक छुड़ाने के लिए 5000 रुपये और कार छुड़ाने के लिए 10000 रुपये का जुर्माना देकर ले जा सकते हैं। दूसरे राज्यों में पंजीकृत ऐसे वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। 10 हजार रुपये का जुर्माना देने के साथ वाहन लाने का कारण भी बताना होगा।

प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड मामले में दोषी की रिहाई पर नया मोड़, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

नईदिल्ली। प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अपना फैसला सुनाते हुए दोषी के समय से पहले रिहाई की याचिका को खारिज करने का फैसला रद्द कर दिया. दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा समीक्षा बोर्ड को दोषी की अपील पर फिर से विचार करने के लिए कहा है. दोषी संतोष कुमार सिंह साल 1996 में लॉ की स्टूडेंट प्रियदर्शिनी मट्टू से रेप और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस संजीव नरूला ने 14 मई को संतोष कुमार सिंह की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस संजीव नरूला ने अपने फैसले में कहा कि दोषी संतोष सिंह में सुधार की भावना है. और उन्होंने दोषी के समय पूर्व रिहाई की याचिका पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को सजा समीक्षा बोर्ड के पास वापस भेज दिया है . अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा की हमें उसमें सुधार की भावना मिली है, एसआरबी के फैसले को खारिज किया जाता है. और इस आधार पर मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए एसआरबी के पास वापस भेज दिया है. कोर्ट ने कैदियों की याचिकाओं पर विचार करते समय एसआरबी द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ दिशा-निर्देश भी तैयार किए है.

कोर्ट ने कहा कि एसआरबी को दोषियों की याचिकाओं पर विचार करते समय उनका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करना चाहिए जो इस मामले में नहीं किया गया. दिल्ली हाई कोर्ट में दोषी संतोष सिंह के तरफ से पेश वकील मोहित माथुर ने दलील देते हुए कहा था कि उनके क्लाइंट का व्यवहार संतोषजनक रहा है जो उनके सुधार का संकेत देता है. और भविष्य में अपराध करने की उनकी संभावना पूरी तरह समाप्त हो चुकी है. दिल्ली हाई कोर्ट में दलील देते हुए उन्होंने यह भी कहा की संतोष सिंह कई सालों से ओपन जेल में है और समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बन सकते हैं. 25 साल की प्रियदर्शिनी मट्टू का जनवरी 1996 में रेप और हत्या कर दी गई थी. दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लॉ स्टूडेंट संतोष कुमार सिंह को इस मामले में आरोपी माना गया था. लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 3 दिसंबर 1999 को संतोष कुमार सिंह को बरी कर दिया. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2006 को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए संतोष कुमार सिंह को प्रियदर्शनी मट्टू की हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी. दोषी संतोष कुमार सिंह जो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी का बेटा है . दोषी संतोष कुमार सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में दोषी संतोष कुमार सिंह की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दी.

कुख्यात बदमाश ललित नेपाली का एनकाउंटर, दो दर्जन से अधिक वारदातों में था शामिल

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक कुख्यात बदमाश ललित नेपाली का एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ में बदमाश ललित नेपाली घायल हो गया। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में लाजपत नगर के एसीपी बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण बाल-बाल बच गए। ललित दो दर्जन से अधिक वारदातों में शामिल था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एसटीएफ और सनलाइट कॉलोनी थाने की संयुक्त कार्रवाई में सराय काले खां बस स्टैंड के पास वांछित अपराधी ललित के साथ मुठभेड़ हुई। करीब दो दर्जन अपराधों में शामिल और कई मामलों में कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित ललित मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया। एसीपी लाजपत नगर अपनी बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से मुठभेड़ में बाल-बाल बच गए। ललित को साकेत थाने में एक मुकदमे में आरोपी को 14 साल की जेल भी हो चुकी थी। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी के पास से एक सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

शिवसेना यूबीटी की पार्टी चुनाव चिन्ह विवाद पर जल्द सुनवाई की मांग, स्थानीय निकाय चुनाव है वजह

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने आज शिवसेना यूबीटी की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में महाराष्ट्र निकाय चुनाव को देखते हुए पार्टी चुनाव चिन्ह पर जल्द फैसला देने की मांग की गई। शिवसेना यूबीटी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि अगर एक बार राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई तो फिर चुनाव चिन्ह में बदलाव नहीं हो सकेगा। पहले से ही यह मामला दो साल से लंबित है। शिवसेना यूबीटी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि विवाद को लेकर अंतरिम निर्देश दिए जाएं। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। अब अदालत 14 जुलाई 2025 को फिर से इस मामले पर सुनवाई करेगी। जून 2022 में अविभाजित शिवसेना टूटकर दो गुटों में बंट गई। जिनमें से एक गुट बना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और दूसरा गुट बना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी। दोनों गुटों ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर दावा किया और मामला चुनाव आयोग के पास गया। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पक्ष में फैसला दिया और उसे असली शिवसेना माना। जिसके बाद शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिला। इस फैसले के खिलाफ शिवसेना यूबीटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान शिवसेना यूबीटी के वकील देवदत्त कामत ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष दलीलें पेश की और पार्टी चिन्ह के मामले पर इस हफ्ते या अगले हफ्ते ही सुनवाई की मांग की।

दिल्ली में समयसीमा पूरे कर चुकी गाड़ियों पर बैन को लेकर आतिशी का हमला, किसी भी वाहन की उम्र का...

नई दिल्ली । दिल्ली में निर्धारित समय से पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लागू होने को लेकर बवाल जारी है. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है कि 10 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा और उन्हें सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी. दिल्ली के आम लोग दफ्तरों में आने-जाने के लिए दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं. अब वे क्या करेंगे? उन्होंने कहा, दूसरी बात, दिल्ली में कई बुजुर्ग लोग स्थानीय इस्तेमाल के लिए सेकेंड हैंड दोपहिया वाहन इस्तेमाल करते हैं. अब वे क्या करेंगे?

क्या वे बुजुर्ग लोग पैदल ही बाजार जाएंगे? यह आदेश निराधार और अतार्किक है क्योंकि किसी भी वाहन की उम्र का उससे होने वाले प्रदूषण से कोई लेना-देना नहीं है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत मंगलवार से दिल्ली के पेट्रोल पंपों को कहा गया है कि जिन वाहनों की समयसीमा पूरी हो गयी हो (ईओएल) उन्हें ईंधन न दें. दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल चालित वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. आतिशी ने कहा, गाड़ियों का उनके पुराने होने और प्रदूषण होने से कोई संबंध ही नहीं है. अगर गाड़ी का सही से रखरखाव किया जाये तो वह प्रदूषण नहीं करती है. बीजेपी सरकार ने यह तुगलकी फरमान गाड़ी निर्माता कंपनियों से सांठगांठ कर दी है. इस फरमान के बाद 62 लाख वाहनों को सड़क से हटना पड़ेगा और नए वाहन खरीदने पड़ेंगे और कंपनियों को फायदा होगा. उन्होंने कहा, बीजेपी बताए कि उन्हें इन वाहन निर्माता कंपनियों से कितना चंदा मिला है, जो उन्होंने यह तुगलकी फरमान जारी किया है, जिससे कंपनियों को फायदा मिलेगा.

चमन कुमार बेच रहा था गाय का मांस, फोरेंसिक जांच में खुलासा

नई दिल्ली । दिल्ली के मॉडल टाउन के विजय नगर इलाके में एक शॉप पर गाय का मांस बिकने का खुलासा हुआ है. इस बात की पुष्टि फोरेंसिक रिपोर्ट में हुई है. करीब एक महीने पहले ये मामला सामने आया था, जिसमें ये शक जताया गया था कि युवक द्वारा बेचा जा रहा मांस गाय का है, वहीं अब इसकी पुष्टि हुई है. दरअसल, मई में एक 15 साल के लड़के ने पीसीआर कॉल की. उसने पुलिस को बताया कि उसने 400 प्रति किलो के हिसाब से विजय नगर की दुकान से मांस खरीदा था. लेकिन उसे शक हुआ कि वो मांस गाय का है. इस शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान से मांस के सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेज दिए. इस दौरान वहां काफी लोग भी इकट्ठा हो गए और चमन कुमार की पिटाई भी की. पुलिस मौके पर पहुंची और चमन कुमार को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया. अलग-अलग संगठनों के सदस्य चमन कुमार की दुकान के बाहर इकठ्ठा हो गए और जमकर हंगामा किया. घटना के पता लगने के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई.

भीगने के लिए तैयार रहें दिल्लीवासी, अब जमकर बरसेंगे बदरा; इतने दिनों तक होगी बारिश

नई दिल्ली । पूरे हफ्ते बारिश दिल्लीवासियों को भिगाएगी। मानसून के आगमन से राजधानी का मौसम खुशनुमा हो गया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले छह से सात दिनों तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे से मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे के बीच राजधानी में 2.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं, बुधवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। ऐसे में बहुत हल्की बारिश गरज के साथ होगी। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मंगलवार सुबह से ही सूरज और बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल जारी रहा। दिन के समय में धूप निकली। हालांकि, दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। लेकिन, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 35.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का न्यूनतम स्तर 64 फीसदी रहा। लोधी रोड में सबसे अधिक तापमान रहा। यहां अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रिज में 34, आया नगर में 33.4 और पालम में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। वहीं, रिज में न्यूनतम तापमान अन्य केंद्र के मुताबिक सबसे कम रहा। यहां न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आया नगर में 25.6, पालम में 24.1 और लोधी रोड में 24.2 डिग्री दर्ज हुआ। इसके अलावा, मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक मयूर विहार में 2.5, पालम में 27.2, आया नगर में 22.6, रिज में 1.4, नजफगढ़ में 11, मानक वेधशाला सफदरजंग में 2.5 और लोधी रोड में बारिश में 1.8 एमएम बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में इस बार जून में 107.1 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य (74.1 मिलीमीटर) से 45 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष जून में 243.4 मिलीमीटर वर्षा हुई थी।

सीएम रेखा गुप्ता को मिला नया सरकारी आवास, PWD ने सजावट और सुरक्षा पर झोंके लाखों रुपये

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं रेखा गुप्ता को राजधानी में दो सरकारी बंगले आवंटित किए गए हैं। इनमें से बंगला नंबर-1 को उनके आधिकारिक निवास के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जबकि दूसरे बंगले का उपयोग उनके कैंप ऑफिस के रूप में किया जाएगा। वर्तमान में रेखा गुप्ता शालीमार बाग स्थित अपने निजी आवास में रह रही हैं। बंगला नंबर-1 की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग ने 28 जून को एक टेंडर जारी किया है। इस काम पर करीब 60 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

रेनोवेशन का पहला चरण मुख्य रूप से बंगले में इलेक्ट्रिकल सिस्टम के इंस्टॉलेशन और अपग्रेडेशन से जुड़ा होगा। PWD अधिकारियों के मुताबिक, यह बंगला पहले उपराज्यपाल सचिवालय का ऑफिस था, इसलिए इसे मुख्यमंत्री के निवास के रूप में उपयोग करने योग्य बनाने के लिए कई जरूरी बदलाव करने होंगे।

सीएम आवास रेनोवेशन- टेंडर में शामिल हैं ये प्रमुख काम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए तैयार किए जा रहे सरकारी आवास के रेनोवेशन टेंडर में कई आधुनिक सुविधाओं को शामिल किया गया है। प्रस्तावित कार्यों में प्रमुख तौर पर ये शामिल हैं

1. एयर कंडीशनर- आवास में कुल 24 एयर कंडीशनर लगाए जाएंगे, जिनकी क्षमता 2 टन होगी। इनमें से 14 एसी की कीमत लगभग 7.7 लाख रुपये होगी, जबकि बाकी एसी मिलाकर कुल खर्च 11.11 लाख रुपये तक पहुंचेगा।
2. स्मार्ट टीवी- घर में कुल 5 स्मार्ट 4K एलईडी टीवी लगाए जाएंगे। इनमें चार 55 इंच के और एक 65 इंच का टीवी होगा। इन पर लगभग 9.3 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
3. सीसीटीवी कैमरे- सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 14 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 5.74 लाख रुपये होगी। सीलिंग फैन- रिमोट से चलने वाले 23 छत वाले पंखे भी लगाए जाएंगे, जिनकी अनुमानित लागत 1.8 लाख रुपये है।

लाइटिंग और सजावट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए सरकारी आवास को सजाने और आधुनिक बनाने के लिए रोशनी व सजावट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बंगले में कुल 115 लाइटिंग यूनिट्स लगाए जाएंगे, जिनमें हैंगिंग लाइट्स, वॉल लाइटर और तीन बड़े झूमर शामिल हैं। इन सभी लाइटिंग उपकरणों पर लगभग 6.03 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। खासतौर पर आम हॉल में 16 फ्लश-सीलिंग लाइट्स, 7 ब्रास लैंटर्न और 8 ब्रास-ग्लास वॉल लाइट्स लगाई जाएंगी, जबकि ड्रॉइंग रूम और प्रवेश द्वार को सजाने के लिए एक बड़ा ब्रास-फ्रेम झूमर और दो छोटे झूमर लगाए जाएंगे।

सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं

सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से भी बंगले को अपग्रेड किया जा रहा है। पूरे परिसर में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से 10 एलईडी फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी और एक नया इंटरकॉम सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, पेयजल सुविधा के लिए 50 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला एक हाई-कैपेसिटी आरओ वाटर प्लांट भी लगाया जाएगा।

टेंडर प्रक्रिया और समय सीमा

इस रेनोवेशन कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया 4 जुलाई को शुरू होगी। टेंडर स्वीकृत होने के बाद अगले 60 दिनों के भीतर सभी काम पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार, शेष सिविल कार्यों और कैंप ऑफिस के निर्माण के लिए अलग से टेंडर जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि बीजेपी ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास में नहीं रहेंगी। उन्हें जो नया बंगला आवंटित किया गया है, वह टाइप-7 श्रेणी का है, जो वरिष्ठ पदाधिकारियों को आवंटित किया जाता है।

सिंगल यूज़ प्लास्टिक के भयंकर नकारात्मक परिणामों व पर्यावरण प्रदूषण को रेखांकित करना

वैश्विक स्तर पर वर्तमान बदलते परिवेश में हम अति तीव्र गति से विकास तो कर रहे हैं, परंतु ठीक उसी अंदाज में ही हमारे लिए पर्यावरण नुकसान के रूप में परेशानियां, विभीषिका, नुकसान की खाई भी बढ़ती जा रही है इसलिए बड़े बुजुर्गों वह बुद्धिजीवियों ने कहा है कि आधुनिक सुख सुविधाओं का उपयोग करने से पहले उनके विपरीत परिणाम के बारे में भी ध्यान रखें, मैं एडवोकेट किशन सनमुख दास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र, ऐसा मानता हूं कि अच्छे इरादों और ढेर सारे नियमों के बावजूद प्लास्टिक के खिलाफ भारत की जंग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ उत्साहजनक संकेत मिल रहे हैं जो यह बताते हैं कि यह लड़ाई अभी हारी नहीं है। तथ्य यह है कि प्लास्टिक अपशिष्ट को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा,यद्यपि व्यापक है, तथापि असंगत परिभाषाओं और छूटों को संबोधित करने के लिए सुधार की आवश्यकता है, जो वर्तमान में प्रवर्तन को कठिन बनाते हैं।संस्कृत श्लोकों में भी आया है पर्यावरणहीन नरपति सर्वजनकल्याण(पवन)दुष्टानां नाति प्रकृतिविकृतयो ।।हिंदी अर्थ- हमारे पर्यावरण के प्रदूषण (विकार) के कारण सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं, हवाएं खराब हो जाती हैं और प्रकृति शत्रुतापूर्ण हो जाती है। आज जिस विषय पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 जुलाई 2025 को प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस है,इसलिए आज हम चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं से पर्यावरण को होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए इसके उपयोग को खुद भी रोकना है और पूरे विश्व को इसके लिए जनजागृत करने में प्रभावी जनभागीदारी पर इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथियों बात अगर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक बैग के दुष्प्रभावों के बारे में जानने की करें तो, प्लास्टिक बैग के बारे में 5 तथ्य (1)प्लास्टिक की थैलियों को विघटित होने में 100 से 500 वर्ष लगते हैं।(2) हम हर साल 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग बनाते हैं।(3) औसत व्यक्ति एक प्लास्टिक बैग का उपयोग 25 मिनट तक करता है। (4) दुनिया भर में हर मिनट हम 10 लाख प्लास्टिक बैग का उपयोग करते हैं। (5) प्लास्टिक थैलियों के कारण हर वर्ष लगभग 1,00,000 समुद्री जीव मारे जाते हैंपर्यावरण को इससे हानिकारक होने के अलावा, प्लास्टिक बैग भी खराब तरीके से डिजाइन किए जाते हैं और शायद ही कभी उनका पुनर्चक्रण किया जाता है। प्लास्टिक बैग हमारे ग्रह के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। हर साल, 8 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक समुद्र में जाकर मछलियों और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाता है। जब प्लास्टिक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है, तो यह मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। साथियों बात अगर हम कुछ देशों द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक व बैगों के दुष्प्रभाव को स्वतंत्र संज्ञान लेकर सख्त कदम उठाने की करें तो,कुछ स्थानों पर किसी भी तरह के प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है या नियम लागू किए गए हैं। ये उपाय करने वाले स्थानों में हवाई, उत्तरी कैरोलिना, इटली, चीन, अफ्रीका के कई देश और ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। कुल मिलाकर, लगभग 127 देश किसी न किसी तरह से प्लास्टिक बैग को नियंत्रित करते हैं। इन नियमों में प्लास्टिक बैग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना और दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले बैग के लिए प्रोत्साहन देना भी शामिल है। ज़्यादातर लोग प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल सिर्फ़ एक बार करते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं।सिंगल -यूज़ प्लास्टिक बैग ने कुछ शहरों को इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया है। जिन जगहों पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथियों बात अगर बिगड़ती पर्यावरण की स्थिति बिगड़ने की करें तो इससे होने वाले दुष्परिणामों पर वैश्विक स्तर सकारात्मक चिंता जा रहा है और उनके अंतरराष्ट्रीय मंचों से पर्यावरण सुरक्षा संबंधी उपायों पर एकजुट निरंतर की संयोजन हो रहा है दुनिया के देशों में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा शून्य करने के बारे में कहा जा रहा है जिसमें पेरिस समझौता महत्वपूर्ण उदाहरण है इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हो,पीआईबी के अनुसार ,चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में, भारत ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें वैश्विक समुदाय द्वारा इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। यूएनईए 4 में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाना एक महत्वपूर्ण कदम था। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के हाल ही में संपन्न पांचवें सत्र में, भारत प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कार्रवाई शुरू करने के संकल्प पर आम सहमति विकसित करने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ा। साथियों बात अगर हम भारत की करें तो, पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16फरवरी, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022 के रूप में प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी पर दिशा-निर्देशों को भी अधिसूचित किया है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दरअसल उत्पाद की शुरुआत से अंत तक उसके पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन के लिए एक उत्पादक की जिम्मेदारी होती है। ये दिशा-निर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, प्लास्टिक पैकेजिंग के नए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देने और कारोबारों द्वारा टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग के विकास की दिशा में कदम बढ़ाने से संबंधित रूपरेखा मुहैया कराएंगे। साथियों बात अगर हम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 की करें तो इसके अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 सितंबर 2021 से और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले इस सामान पर 31 दिसंबर, 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है। जिसमें हाल ही में संशोधन कर 150 माइक्रोन कर दिया गया है। साथियों बात अगर हम माननीय पीएम के आह्वान की करें तो, उन्होंने 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने के लिए दिए गए स्पष्ट आह्वान के अनुरूप, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया। आजादी के अमृत महोत्सव की भावना को आगे बढ़ाते हुए, देश द्वारा कूड़े एवं अप्रबंधित प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से एक निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। भारत 1 जुलाई, 2022 से पूरे देशमें चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम और प्रदूषण क्षमता अधिक है, के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। साथियों बात अगर हम सिंगल यूज़ उपयोग वाली वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की सूची की करें तो भारत सरकार ने, सिंगलयूज़ प्लास्टिक्सो उत्पन्न कचरेसे होने वालेप्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में ये वस्तुएं शामिल हैं- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक,सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल), प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर,स्टिरर। साथियों बात अगर हम नियमों को ठोस कार्रवाई के माध्यम से लागू करने की करें तो, 1 जुलाई 2022 से चिन्हित एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे तथा प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग की निगरानी के लिए विशेष प्रवर्तन दल गठित किये जायेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के अंतर-राज्य परिवहन को रोकने के लिए सीमा जांच केंद्र स्थापित करने के लिए कहा गया है। सरकार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को समाप्त करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। जागरूकता अभियान में उद्यमियों और स्टार्ट अप्स, उद्योग, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों नियामक निकायों, विशेषज्ञों, नागरिक संगठनों, अनुसंधान एवं विकास और अकादमिक संस्थानों को एकजुट किया गया है।

जीडीपी के आंकड़े बनाम असली तरक़्क़ी

प्रभात पटनायक

वाणिज्यवादी किसी राष्ट्र की संपन्नता को उसके पास बहुमूल्य धातुओं की मात्रा से आंका करते थे और राष्ट्र की प्रगति को उसके पास इन बहुमूल्य धातुओं की मात्रा में बढ़ोतरी से आंकते थे। इन बहुमूल्य धातुओं की अपनी इस मात्रा में बढ़ोतरी के लिए, संबंधित राष्ट्र के लिए माल तथा सेवाओं के व्यापार का संतुलन अनुकूल या बचत वाला होने यानी उसके निर्यात के आयात से ज्यादा होने की अपेक्षा होती थी और इस व्यापार बचत का निपटारा बहुमूल्य धातुओं, खासतौर पर सोने के आयात के जरिए होता था और इस तरह संबंधित देश के पास सोने की मात्रा बढ़ने की उम्मीद की जाती थी। अपने महाग्रंथ, द वैल्थ ऑफ नेशन्स में एडम स्मिथ ने इन वाणिज्यवादियों को ही निशाना बनाया था। स्मिथ का कहना यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी व्यापार इजारा कंपनियां जो दावा करती थीं उसके विपरीत, बहुमूल्य धातुओं के भंडारों से किसी राष्ट्र की संपदा परिभाषित नहीं होती थी। इसके बजाए किसी देश के पास कितना पूंजी स्टॉक था, उससे राष्ट्र की संपदा परिभाषित होती थी। इसलिए, किसी राष्ट्र की संपन्नता पूंजी के ज्यादा से ज्यादा स्टॉक जमा करने में निहित होती है और इसके लिए सबसे अनुकूल स्थितियां बाजारों तथा पूंजी के काम-काज पर राज्य द्वारा लगायी जाने वाली सभी बंदिशों के हटाए जाने से पैदा होती हैं। यानी इसके लिए अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार की परिस्थितियां सुनिश्चित किए जाने की जरूरत होती है। और इसे संभव बनाने के लिए, शासन पर से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी इजारेदाराना कंपनियों का शिकंजा खत्म किया जाना जरूरी है। स्मिथ के रुख के संबंध में ध्यान खींचने वाली बात यह थी अपने से पहले की अवधारणा से क्रांतिकारी पथ-परिवर्तन के बावजूद, वह रुख राष्ट्र पर ही केंद्रित बना रहता है, न कि जनता पर।

इसमें राष्ट्र की संपदा को एक ऐसी सत्ता माना जाता है, जो जनता से ऊपर है और जिसे अभीष्ट के तौर पर गिना जाता है। इस तरह, संपदा के रूप में किसे गिना जाना चाहिए, इसकी अवधारणा बदल जाती है और सोने तथा चांदी की जगह पर, पूंजी स्टॉक की गिनती होने लगती है, लेकिन वह सत्ता नहीं बदलती है, जिसकी संपदा की बात की जा रही होती है। यह विचार कि राष्ट्र, जनता से अलग है और वह जनता से ऊपर है, उस पूंजीवादी राष्ट्रवाद की विशेषता था, जो वैस्टफेलियाई शांति संधियों के बाद यूरोप में विकसित हुआ था। जहां यह पूंजीवादी राष्ट्रवाद, 1930 के दशक में यूरोपीय फासीवाद के अंतर्गत अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था, यह विचार अपने आप में वह सामान्य सूत्र था, जो पूंजीवादी विचार की समूची यात्रा में समाया नजर आता है। बेशक, चूंकि राष्ट्र कथित रूप से अपनी जनता से ऊपर था, ''राष्ट्रीय हित'' की पहचान अनिवार्य रूप से पूंजीपति वर्ग के खास हिस्सों के हितों के रूप में की जाती थी। इस प्रकार वाणिज्यवाद से एडम स्मिथ तक का बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी इजारेदाराना व्यापारी कंपनियों के हितों की, ''राष्ट्रीय हित'' के समानार्थी के रूप में पूजा की जगह पर, उदीयमान विनिर्माता पूंजीपति वर्ग के हितों को ''राष्ट्रीय हित'' के मूर्त रूप के तौर पर स्थापित करता है।

अब पूंजीपति वर्ग के इस बाद वाले हिस्से के हितों का आगे बढ़ाया जाना, राष्ट्र के हितों के आगे बढ़ाए जाने का समानार्थी बन जाता है। लेकिन, यह बदलाव करते हुए हमेशा, राष्ट्र की एक ऐसी अवधारणा पर कायम हो जा रहा था, जिसके हितों को आगे बढ़ाया जाना था और जो एक ऐसी सत्ता थी जो जनता से भिन्न थी और उससे ऊपर थी। डेविड रिकार्डो की प्रगति की ठीक यही धारणा थी, जो एडम स्मिथ की थी और वह थी, राष्ट्र में पूंजी स्टॉक का संचय। उनका यह डर कि पूंजीवादी व्यवस्था एक अचल अवस्था की ओर चली जाएगी, जहां पूंजी संचय होना बंद हो जाएगा, ठीक इसी धारणा से निकलता था कि पूंजी स्टॉक , किसी राष्ट्र की संपदा होते हैं। उनकी नजर में पूंजी संचय के रुकने का अर्थ होगा, प्रगति का अंत। जॉन स्टुअर्ट मिल बेशक इस लिहाज से एक अपवाद थे। वह यह कहते थे कि अचल अवस्था की परवाह करने की जरूरत नहीं है, अगर उसके अंतर्गत मजदूर उस स्थिति के मुकाबले बेहतर स्थिति में हों, जब अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय हो रहा हो। यानी स्मिथ तथा रिकार्डो जैसे अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, मिल मजदूरों के कल्याण को पूंजी के संचय के ऊपर रखते हैं। लेकिन, क्लासिकी राजनीतिक अर्थशास्त्र के रुख से इस विचलन को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि अपनी पत्नी हैरियट के प्रभाव से वह एक खास समाजवादी रुख की ओर बढ़ रहे थे। बहरहाल, अभीष्ट के रूप में, राष्ट्र की मेहनतकश आबादी की खुशहाली की जगह पर, पूंजी स्टॉक की मात्रा पर और उससे पैदा होने वाले उत्पाद की मात्रा पर ही ध्यान केंद्रित करने के लिए, स्मिथ तथा रिकार्डो जैसे क्लासिकी अर्थशास्त्रियों की ज्यादा सख्ती से आलोचना नहीं की जानी चाहिए। मजदूरों के प्रति उनकी भी काफी सहानुभूति थी, लेकिन वे यह मानते थे कि अगर उनकी माली हालत बेहतर होती है, तो मजदूर ज्यादा तेजी से संतानोत्पादन करते हैं। यह वही विचार था जिसकी अभिव्यक्ति आबादी के संबंध में माल्थस के सिद्धांत में हुई थी। उनका मानना था कि अगर वास्तविक मजदूरी, गुजारे के स्तर से बढ़ जाएगी, तो आबादी भी बढ़ जाएगी और इसलिए श्रम की आपूर्ति भी बढ़ जाएगी। और यह वास्तविक मजदूरी को वापस गुजारे के स्तर पर धकेल देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मजदूरों की जीवन दशा में कोई भी सुधार, खुद उनके ऊपर ही निर्भर करता है। यानी अगर वे अपनी आदतें बदल लेते हैं तथा अपनी जीवन दशा में सुधार होने पर भी अपनी आबादी में बढ़ोतरी को अंकुश में रख सकते हैं, तभी वे अपनी माली हालत में हुए सुधार को बनाए रख सकते हैं। चूंकि नीति इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है, नीति का ध्यान तो कुल पूंजी स्टॉक को और इस तरह उत्पाद को बढ़ाने पर ही लगा रहना चाहिए। इससे, सब के लिए उपलब्ध कुल राशि बढ़ जाएगी और मजदूरों को इससे कहीं बड़ा हिस्सा मिल सकेगा, बशर्ते वे अपनी आदतें बदल लें। बहरहाल, स्मिथ और रिकार्डो के मामले में हम जिस तरह की नरमी अपना सकते हैं, वैसी ही नरमी के तथाकथित ''मुख्यधारा'' के अर्थशास्त्र के साथ नहीं बरती जा सकती है। आबादी के माल्थस के सिद्धांत में विश्वास का अंत बहुत पहले ही चुका था।

वास्तव में मार्क्स ने इस सिद्धांत को ''मानव जाति का कलंक'' कहा था, उससे अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध तथा उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के विपरीत, आज कहीं ज्यादा आम सहमति होगी। लेकिन, इसके बावजूद ''मुख्यधारा'' का पूंजीवादी सिद्धांत अब भी कुल उत्पाद के स्तर को किसी ''राष्ट्र'' की खुशहाली का सूचक मानता है और उसकी वृद्धि दर को प्रगति का सूचक मानता है। चूंकि इस अर्थ में प्रगति तो पूंजीपतियों की गतिविधियों से ही हासिल को जा सकती है, इसका अर्थ यह हुआ कि ''राष्ट्र'' का बेहतरीन हित इसी में है कि पूंजीपतियों को खुश रखा जाए, उन्हें प्रोत्साहन दिए जाएं, उनके हितों को आगे बढ़ाया जाए और उनके साथ विशेषाधिकार-प्राप्त लोगों वाला सलूक किया जाए। स्मिथ और रिकार्डो ने फिर भी, जाहिर है कि गलती से मगर यह सोचने के चलते इस तरह का रुख अपनाया हो सकता है कि जब तक मजदूर ही अपनी आदतें नहीं बदल लेते हैं, इसके सिवा और कुछ किया ही नहीं जा सकता था। लेकिन, बाद के अर्थशास्त्रियों का इस तरह का रुख अपनाना, शुद्ध विचारधारात्मक पूर्वाग्रह को ही दिखाता है। इस पूर्वाग्रह की तात्कालीन मिसाल नीति आयोग के सीईओ की इसकी घोषणा है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अपने जीडीपी के आकार के हिसाब से उसने अब, 4 ट्रिलियन (या 40 खरब) डालर का आंकड़ा पार कर, हाल ही में जापान को पछाड़ दिया है। नीति आयोग के सीईओ ने सिर्फ चलते-चलाते यह बात नहीं कह दी। उन्होंने बाकायदा एक बड़ी भारी उपलब्धि के रूप में इसका ढोल पीटा और हैरानी की बात नहीं है कि भारत के बड़े कारोबारी हलके सदस्यों ने इसकी तारीफों के पुल बांधे हैं। बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि नीति आयोग के सीईओ ने इस तथ्य का जिक्र तक नहीं किया कि भारत की आबादी, जापान के मुकाबले दस गुनी से ज्यादा है। नीति आयोग के सीईओ उसी तरह इसका बखान कर रहे थे, जैसे अब से कुछ ही अर्सा पहले नरेंद्र मोदी यह कह रहे थे कि भारत का जीडीपी जल्द ही 5 ट्रिलियन (50 खरब) डालर हो जाएगा।

बहरहाल, देश के आकार के अलावा, जो हमारे देश के जीडीपी के कुल आकार की विकसित पूंजीवादी देशों के साथ तुलना पर आधारित ऐसे सभी दावों को निरर्थक बना देता है, जीडीपी पर ही ध्यान केंद्रित करना पूरी तरह से झूठे परिप्रेक्ष्य को दिखाता है। यह न सिर्फ उस पुराने परिप्रेक्ष्य पर लौटना है, जो कभी माल्थसवाद में विश्वास किया करता था, बल्कि यह एक जनतांत्रिक समाज से पूरी तरह से बेमेल भी है। जनतंत्र में जनता की दशा से ही फर्क पड़ता है और प्रगति को पूरी तरह से इसी के पैमाने से नापा जाना चाहिए कि जनता की दशा में कितना सुधार हो रहा है। यह परिप्रेक्ष्य हमारे उपनिवेश-विरोधी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से भी मेल नहीं खाता है। ''राष्ट्र'' की वह अवधारणा, जिसके जीडीपी के मामले में जापान को पछाड़ देने की खुशी मनाने का मौका बताया जा रहा है, एक ऐसे राष्ट्र की अवधारणा है, जो अपनी जनता से ऊपर है, जिसकी ''शानदार'' उपलब्धि का, जनता की जीवन दशाओं से कुछ लेना-देना ही नहीं है। यह पूरी तरह से उस उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष की भावना के लिए अभिशाप है, जो साम्राज्यवादी शासन से ''राष्ट्र'' की मुक्ति को, उसकी जनता की मुक्ति का समानार्थी मानती थी। बहरहाल, आजादी की तीन-चौथाई सदी से ज्यादा के बाद भी, न सिर्फ जनता की दशा करीब-करीब पहले जितनी ही दयनीय बनी हुई है और जिन 127 देशों के लिए वैश्विक भूख सूचकांक तैयार किया जाता है।

सम्पादकीय...

मध्यमवर्गीय फंसे ऋण के जाल में

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी की है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड कम्पनियों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों ने भी अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी की घोषणा करना प्रारम्भ कर दिया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कमी का लाभ शीघ्र ही भारत में ऋणदाताओं तक पहुंच सके एवं इससे अंततः देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। भारत में चूंकि अब मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रण में आ गई है, अतः आगे आने वाले समय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में और अधिक कमी की जा सकती है। इस प्रकार, बहुत सम्भव है ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी के बाद कई नागरिक जिन्होंने पूर्व में कभी बैंकों से ऋण नहीं लिया है, वे भी ऋण लेने का प्रयास करें। बैंक से ऋण लेने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस ऋण को चुकता करने की क्षमता भी ऋणदाता में होनी चाहिए अर्थात ऋणदाता की पर्याप्त मासिक आय होनी चाहिए ताकि बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की किश्त एवं ब्याज का भुगतान पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके। इस संदर्भ में विशेष रूप से युवा ऋणदाताओं द्वारा क्रेडिट कार्ड के उपयोग पश्चात संबंधित राशि का भुगतान समय सीमा के अंदर अवश्य करना चाहिए क्योंकि अन्यथा क्रेडिट कार्ड एजेंसी द्वारा चूक की गई राशि पर भारी मात्रा में ब्याज वसूला जाता है, जिससे युवा ऋणदाता ऋण के जाल में फंस जाते हैं। बैंकों से लिए गए ऋण की मासिक किश्त एवं इस ऋणराशि पर ब्याज का भुगतान यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं किया जाता है तो चूककर्ता ऋणदाता से बैंकों द्वारा दंडात्मक ब्याज की वसूली की जाती है। इसी प्रकार, कई नागरिक जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं एवं इस क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की गई राशि का भुगतान यदि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं कर पाते हैं तो इस राशि पर चूक किए गए क्रेडिट कार्ड धारकों से भारी भरकम ब्याज की दर से दंड वसूला जाता है। कभी कभी तो दंड की यह दर 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच रहती है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले नागरिक कई बार इस उच्च ब्याज दर पर वसूली जाने वाली दंड की राशि से अनभिज्ञ रहते हैं। अतः बैंकों से ली जाने वाली ऋणराशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का समय पर भुगतान करने के प्रति ऋणदाताओं को सजग रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह ऋणदाताओं के हित में है कि वे बैंक से लिए जाने वाले ऋण की राशि तथा ब्याज की राशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का पूर्व निर्धारित एवं उचित समय सीमा के अंदर भुगतान करें क्योंकि अन्यथा की स्थिति में उस चूककर्ता नागरिक की क्रेडिट रेटिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं आगे आने वाले समय में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है एवं बहुत सम्भव है कि भविष्य में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त हो न हो सके। ऋणदाता यदि किसी प्रामाणिक कारणवश अपनी किश्त एवं ब्याज का बैंकों अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को समय पर भुगतान नहीं कर पाता है और उसका ऋण खाता यदि गैर निष्पादनकारी आस्ति में परिवर्तित हो जाता है तो इस संदर्भ में चूककर्ता ऋणदाता द्वारा बैंकों को समझौता प्रस्ताव दिए जाने का प्रावधान भी है। इस समझौता प्रस्ताव के माध्यम से चूककर्ता ऋणदाता द्वारा सम्बन्धित बैंक अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को मासिक किश्त एवं ब्याज की राशि को पुनर्निर्धारित किए जाने के सम्बंध में निवेदन किया जा सकता है। परंतु, यदि ऋणदाता ऋण की पूरी राशि, ब्याज सहित, अदा करने में सक्षम नहीं है तो चूक की गई राशि में से कुछ राशि की छूट प्राप्त करने एवं शेष राशि को एकमुश्त अथवा किश्तों में अदा करने के सम्बंध में भी समझौता प्रस्ताव दे सकता है। ऋण की राशि अथवा ब्याज की राशि के सम्बंध के प्राप्त की गई छूट की राशि का रिकार्ड बनता है एवं समझौता प्रस्ताव के अंतर्गत प्राप्त छूट के चलते भविष्य में उस ऋणदाता को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान चूककर्ता ऋणदाता को रखना चाहिए। अतः जहां तक सम्भव हो ऋणदाता द्वारा समझौता प्रस्ताव से भी बचा जाना चाहिए एवं अपनी ऋण की निर्धारित किश्तों एवं ब्याज का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भुगतान करना ही सबसे अच्छा रास्ता अथवा विकल्प है। भारत में तेज गति से हो रही आर्थिक प्रगति के चलते मध्यमवर्गीय नागरिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिनके द्वारा चार पहिया वाहनों, स्कूटर, फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन एवं मकान आदि आस्तियों को खरीदने हेतु बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जा रहा है। कई बार मध्यमवर्गीय परिवार एक दूसरे को देखा देखी आपस में होड़ करते हुए भी कई उत्पादों को खरीदने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे उस उत्पाद विशेष की आवश्यकता हो अथवा नहीं। उदाहरण के लिए एक पड़ौसी ने यदि अपने चार पहिया वाहन का एकदम नया मॉडल खरीदा है तो जिस पड़ौसी के पास पूर्व में ही चार पहिया वाहन उपलब्ध है वह पुराने मॉडल के वाहन को बेचकर पड़ौसी द्वारा खरीदे गए नए मॉडल के चार पहिया वाहन को खरीदने का प्रयास करता है और बैंक के ऋण के जाल में फंस जाता है। यह नव धनाढ्य वर्ग यदि बैंक से लिए गए ऋण की किश्त एवं ब्याज की राशि का निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं कर पाता है तो उस नागरिक विशेष के वित्तीय रिकार्ड पर धब्बा लग सकता है जिससे उसके लिए उसके शेष जीवन में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से पुनः ऋण लेने में कठिनाई आ सकती है। अतः बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले नागरिकों को ऋण की किश्त का समय पर भुगतान करना स्वयं उनके हित में है, ताकि भारत में तेज हो रही आर्थिक प्रगति का लाभ आगे आने वाले समय में भी समस्त नागरिक ले सकें। भारत में तो यह कहा भी जाता है कि जिसके पास जितनी चादर हो, उतने ही पैर पसारने चाहिए। अर्थात, नागरिकों को बैंकों से ऋण लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऋण की किश्त एवं ब्याज की राशि का भुगतान करने लायक उनकी अतिरिक्त आय होनी चाहिए, ताकि ऋण की किश्तों एवं ब्याज की राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके एवं उनका ऋण खाता गैर निष्पादनकारी आस्ति में परिवर्तित नहीं हो।

सुरक्षित हवाई यात्रा के लिए बने नई व्यवस्था

12 जून को 230 सवारियों वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी। तीस सेकेंड बाद बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर पड़ा। उस हादसे को रोका जा सकता था, दुर्घटना ने उस विमान की बदहाली की पोल तो खोली ही, विमानन क्षेत्र से जुड़े पूरे तंत्र में व्याप्त सड़ांध को भी उजागर कर दिया। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे हादसे जागने का अवसर होते हैं लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसके बजाय मृतकों के शोकाकुल परिजन शवों की तस्वीरों और अनुत्तरित प्रश्नों के साथ एक से दूसरे मुर्दाघर में दौड़ रहे थे। संकट के समय मदद करने के लिए कोई टीम नहीं थी। एयरलाइंस द्वारा हत्या करके बच निकलने का मुख्य कारण यह है कि उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई विनियामक नहीं है। सच तो यह है कि वह कोई हादसा नहीं था, वह दैनंदिन अक्षमता के वेश में सुनियोजित लापरवाही थी। भारत का विमानन क्षेत्र ऊंची उड़ान नहीं भर रहा, यह विनियंत्रण के स्तर पर डरे होने, कॉरपोरेट लालच और राजनीतिक उदासीनता का मिलाजुला रूप है। नतीजतन रनवे पर, हवा में और जिम्मेदार लोगों के हाथों में-सर्वत्र खून है, दो कंपनियों के नियंत्रण वाला विमानन क्षेत्र सिर्फ एयरलाइंस का संचालन नहीं कर रहा, लोगों के मुताबिक, 35,000 फीट की ऊंचाई पर यह उगाही का तंत्र चलाता है। इन दो प्रमुख एयरलाइन समूहों का भारतीय आकाश के 88.5 फीसदी हिस्से पर कब्जा है। विमानों के किराये का नमूना देखिये = दिल्ली-चंडीगढ़ के बीच 50 मिनट की उड़ान के 8,500 रुपये, चेन्नई से कोयंबटूर के लिए 10,200 रुपये, पिछले साल इंडिगो ने 11.8 करोड़ मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाया और 7258 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। एयर इंडिया हिसाब-किताब के मामले में शालीनता दिखाती है लेकिन एक बार में 470 विमानों के ऑर्डर देने का फैसला उसकी ताकत के बारे में बताता है। गो फर्स्ट के खत्म हो जाने और स्पाइसजेट की हिस्सेदारी घटकर चार फीसदी रह जाने के बाद भारतीय विमानन क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है-सिर्फ कार्टेल पूंजीवाद है और विनियामक? जरा रुकिए, भारत में कोई विनियामक नहीं है। यहां डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय है, नागर विमानन के लिए डीजीसीए का होना वैसा ही है, जैसे चाकू की जगह टूथपिक हो। भारत का तथाकथित विमानन विनियामक फंड और संसाधन की कमी के साथ राजनीतिक अंकुश से जूझ रहा है, इसमें 53 फीसदी पद खाली हैं, जबकि संसाधनों में 91 फीसदी कटौती की गयी है। नींद से जागकर 24 जून को उसने जो जांच रिपोर्ट जारी की, वह डरावने उपन्यास की तरह लगता था।

उसने रिपोर्ट में व्यवहार के अयोग्य बैगेज ट्रॉली, गलत ढंग से रखे लाइफ वेस्ट्स, सुरक्षा के प्रोटोकॉल की अनदेखी, लगातार होने वाली तकनीकी चूक आदि का जिक्र किया है। डीजीसीए ने इन कमियों पर क्या रुख दिखाया? उसने एक प्रेस रिलीज जारी की, अपनी पीठ थपथपायी, फिर लंबी नींद में सो गया। भारत बड़े विमानन बाजार वाला इकलौता देश है, जिसके पास वैधानिक रूप से और स्वतंत्र विनियामक नहीं है। ब्रिटेन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और पड़ोसी नेपाल तक में ऐसे स्वतंत्र निकाय हैं, जिन्हें विमानों पर उड़ान प्रतिबंध लगाने, जुर्माना लगाने, यात्री अधिकारों को लागू करने, यहां तक कि अधिकारियों को जेल में डालने के लिए भी मंत्रियों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका के संघीय विमानन प्राधिकरण (एफएए) में 45,000 कर्मचारी हैं और उसका 20 अरब डॉलर का सालाना बजट है, भारत में डीजीसीए समय पर हादसे की रिपोर्ट जारी कर दे तो यही बहुत है।

दूसरे देशों में विमान दुर्घटनाओं के बाद सुधार लागू होते हैं, वर्ष 2008 के स्पेन एयर हादसे के बाद यूरोपीय संघ ने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया। वर्ष 2018-19 में 737 मैक्स हादसे के बाद एफएए ने बोइंग जेट्स पर 20 महीने का उड़ान प्रतिबंध लगाने के साथ बदलाव भी किये। वर्ष 2023 में विमान के इंजनों का मुद्दा सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलिया का सीएएसए हरकत में आया। जापान में इसी साल टोक्यो के रनवे में हुई टक्कर के तुरंत बाद जेटीएसबी सक्रिय हो गया। अपने यहां अहमदाबाद विमान हादसे के दो सप्ताह बाद तक डीजीसीए चुप रहा। भारतीय विमानन क्षेत्र में सिर्फ फेयर मीटर ही तेज दौड़ता है। हां, हमारे यहां एयरपोर्ट क्वालिटी के लिए विनियामक है, क्योंकि रनवे के टहलते यात्रियों के जीवन से ज्यादा महत्व रखते हैं। विगत मार्च में कोलकाता से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक उड़ान को खराब मौसम के कारण जब जयपुर में उतारा गया तो एक यात्री प्रिया शर्मा अपने पिता के अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं हो सकी। बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही उड़ान में जब एक महिला बेहोश हो गयी तो क्रू ने उसकी अनदेखी की, तब महिला की बेटी को रोते हुए बताना पड़ा कि यह मेरी मां है। पिछले महीने गुवाहाटी से चेन्नई जा रहे इंडिगो के एक विमान के पायलट ने ईंधन भरने के लिए मे डे कॉल किया। दिल्ली से श्रीनगर जा रहा एक विमान ओलावृष्टि से जर्जर हो गया। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक साल में बर्ड हिट के 462 मामले पाये गये। अहमदाबाद हादसे के बाद भारत को बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, इसे सुधार के लिए जुबानी वादे की जरूरत नहीं है। न ही किसी कमेटी या 700 पेज की रिपोर्ट की जरूरत है। इस मौजूदा व्यवस्था को खत्म कर नई व्यवस्था शुरू करनी होगी। देश को एक स्वतंत्र नागर विमानन विनियामक प्राधिकरण की जरूरत है जो पूरी तरह वैधानिक हो, जिसके पास अधिकार हो और जिस पर राजनीतिक दखल न हो। इस प्राधिकरण को विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त करने दें। इसके पास बड़ा बजट हो, किराये के मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। उड़ानों और यात्रियों के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने वाले सीईओ को जेल क्यों नहीं भेजा जाता? यात्रियों के साथ मानवीय सलूक होना चाहिए और संकट के समय किराया घटाया जाना चाहिए, हर हादसे, डायवर्जन या इमर्जेंसी लैंडिंग के ऑडिट का कानून बनाया जाना चाहिए। बीमा राशि सालों बाद नहीं, कुछ हफ्ते बाद मिल जानी चाहिए। उड़ान के दौरान जहरीले खान-पान और उद्दंड क्रू मेंबर्स पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हर विमान हादसे के पीछे खराब मौसम या तकनीकी गलती को कारण बताया जाता है।

जब बार-बार संविधान की हत्या की बात की जाए!

अभी हाल ही में पटना के गांधी मैदान पर वक्फ संशोधन बिल को कूड़े में फेंकने की बात की गई, जो संविधान की हत्या से कम नहीं थी, ठीक ऐसे ही जैसे 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। पटना में सभी विरोधी पार्टियों ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि वे वक्फ संशोधन बिल को गैर कानूनी समझते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि जो बिल संसद में पास हो गया उसे कुछ लंपटवादी के कारण असंवैधानिक करार दिया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी और कानून के कुछ लचर पहलुओं ने मजाक बना रखा है संविधान का। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलेगा कि अगस्त 1975 में अपनी सुरक्षा के लिए संविधान संशोधन करने के पश्चात इंदिरा गांधी और संजय गांधी लग गए अपने अगले लक्ष्य की ओर। दो बातें खास तौर से इनको साध्य करनी थीं। प्रथम तो बचे-खुचे विपक्षियों को और संघ के स्वयंसेवकों को समाप्त करना और ऐसी दहशत निर्माण करना कि देश के किसी भी नागरिक को सरकार के विरोध में बोलने की हिम्मत ही ना हो। द्वितीय, यह कि नसबंदी द्वारा जनसंख्या कम करके इस देश को सुंदर बनाना। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम स्वामी, दत्तोपंत ठेंगड़ी, सिकंदर बख्त, विजय गोयल आदि भूमिगत थे। अनेक संघ के प्रचारक सरकार के हाथ नहीं लगे थे। इनको गिरफ्तार तो करना ही था, साथ ही दहशत भी पैदा करनी थी। असल में पूर्ण देश को जकड़ने की साजिश थी यह। कांग्रेस कैसी दहशत पैदा करती थी, उसका उदाहरण है कि 7 अप्रैल 1976 के दिन, »दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन« के चुनाव हुए। अब बार एसोसिएशन क्यों न हो, दहशत के इस माहौल में क्या और कैसे चुनाव हो सकते हैं, इसलिए इस चुनाव में कांग्रेसी चेले, डी.डी. चावला बड़े ही सहजता से जीत जाएंगे, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लग रहा था, पर हुआ उल्टा। डी.डी. चावला को पटखनी देकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद संघ के स्वयंसेवक, प्राणनाथ लेखी जीतकर आए। यही किस्सा »जिला बार एसोसिएश«' में दोहराया गया। वहां पर भी कंवरलाल गुप्ता चुनकर आए, क्योंकि जनता तब भी परिपक्व थी और उसको अच्छाई का आभास था। फिर क्या था, कांग्रेस का खून खौला। उसने दूसरे ही दिन कोर्ट परिसर में बुलडोजर भेज दिए। जिला और सेशंस कोर्ट के आसपास अनेक वकीलों के कार्यालय थे। पार्टी के आदेश पर उस दिन 1000 से ज्यादा कार्यालयों पर बुलडोजर चलाया गया। यह छुट्टी का दिन था। जैसे ही वकीलों को पता चला, वह भागते-दौड़ते आए, अपना सामान, कागजात बचाने, पर कुछ नहीं हो सका। पुलिस ने उन्हें बड़ी निर्ममता से लाठी मार-मार के भगाया। वकीलों में आक्रोश निर्माण हुआ। दूसरे ही दिन इस घटना का विरोध करने के लिए कुछ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश टी.वी.आर. ताताचारी को ज्ञापन देने का निश्चय किया। ज्ञापन देने वह 43 सीनियर एडवोकेट्स एक बस से जा रहे थे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00882)

एनडीए ही लौटा सकता है बिहार का खोया गौरव

पटना ।बिहार चुनाव से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना के दौरे पर हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश फूंका और उनको जीत का मंत्र दिया। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा में हर कोई कार्यकर्ता की भावना से काम करता है, चाहे वह किसी भी पद पर हो। यही हमारी पार्टी की मजबूती का आधार है और इसी का परिणाम है कि भाजपा आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हुई है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि यह केवल एक संगठन की बैठक नहीं है, बल्कि उस संकल्प की पूर्ति के लिए एक संकल्प सभा है, जिसे हमें बिहार और भारत दोनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लेना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी

ने पिछले 11 वर्षों में दिखाया है कि भारत बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व मजबूत हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। हमें बिहार के हर निवासी के दिल में यही विश्वास जगाना है। राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का एक ही उद्देश्य है, सत्ता में बने रहना। जबकि भाजपा का उद्देश्य

आरजेडी -कांग्रेस ने राज्य को पिछड़ेपन और अपराध की गर्त में धकेला- राजनाथ

भारत के हर नागरिक के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है...ऐसी नीतियां बनाना है जिसमें समाज के हर वर्ग का विकास हो। सभी को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, यह भी हमारी सरकार ने किया है।

उन्होंने कहा कि हम सभी भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत हैं। राजनाथ ने कहा कि लालूजी के मुख्यमंत्री रहते समय कर्पूरी जी की विरासत और मूल्यों दोनों को हाशिए पर डाल दिया गया। यहाँ तक की न कोई स्मृति स्थल, न कोई ठोस योजना उनके नाम पर, न कोई विचारधारा का प्रचार। मोदी जी ने न सिर्फ कर्पूरी जी का नाम नई पीढ़ी को फिर से याद दिलाया, बल्कि उनकी जीवन शैली और सिद्धांतों को 21वीं सदी की राजनीति का आदर्श बनाया।

लालू यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महापुरुषों का अपमान करना कुछ दलों की आदत बन चुकी है। सम्मान देना तो दूर, उन्हें अपनी राजनीति की चौखट पर बिठा देना ही इनकी शैली है। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला एक दृश्य वायरल हुआ, जिसमें लालू जी के जन्मदिन समारोह में बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लालू यादव जी के पैरों के पास रखी गई। आरजेडी जैसे दल बाबासाहेब की तस्वीर ही नहीं उनके विचारों को भी कोई मोल नहीं देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबासाहेब और उनके दिए मूल्यों को अपने दिल में बसाती है। भाजपा की सरकार ने बाबासाहेब से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बिहार को पिछड़ेपन, बेरोजगारी और अपराध की गर्त में धकेला। उन्होंने सत्ता को जनसेवा का माध्यम नहीं, परिवार सेवा का साधन बना दिया। आज जब एक नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है, तो हमारा कर्तव्य है कि उन्हें सच्चाई से परिचित कराएँ। उन्हें बताएं कि अगर बिहार को कोई बदनाम कराता रहा तो वो यही दल थे और अगर बिहार को कोई नया भविष्य दे सकता है, तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है।

मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, कोई शक नहीं...', सिद्धरमैया का बड़ा बयान- कहा- डीके शिवकुमार ने भी दिया साथ

नई दिल्ली । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को कहा कि वह पूरे पांच साल तक पद पर बने रहेंगे। पत्रकारों ने सिद्धरमैया से सवाल किया कि क्या वह पांच साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे जिसके जवाब में वरिष्ठ नेता ने कहा, ''हां, मैं रहूंगा। आपको इसमें संदेह क्यों है? राजनीतिक हलकों में, विशेषकर सत्तारूढ़ कांग्रेस में, सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के बीच सत्ता-साझाकरण समझौते का हवाला देते हुए इस वर्ष के अंत में मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

शिवकुमार ने हालांकि मंगलवार को कहा था कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं हुई और उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया एवं पार्टी की सरकार के हाथ मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री को

बदले जाने संबंधी भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) और जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के नेताओं के दावे को लेकर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, ''क्या वे हमारे आलाकमान हैं?

उन्होंने पूछा, ''आर अशोक (विधानसभा में विपक्ष के नेता) भाजपा के नेता हैं। बी वाई विजयेंद्र (भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष) भाजपा के नेता हैं। चलवाडी नारायणस्वामी (विधान परिषद में विपक्ष के नेता) भाजपा के नेता हैं। अगर वे ऐसी बातें कहेंगे तो क्या आप लिखेंगे? आपको इसकी पुष्टि करनी चाहिए या नहीं? शिवकुमार ने बेंगलुरु में संकटदाताओं से कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर कोई असंतोष नहीं है और जब सिद्धरमैया राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो नेतृत्व के मुद्दे पर किसी विवाद की जरूरत नहीं है। मई 2023 में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी और कांग्रेस शिवकुमार को मनाने में कामयाब रही तथा उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय कुछ खबरें थीं कि क्रमिक मुख्यमंत्री फॉर्मूले के आधार पर समझौता हुआ है जिसके अनुसार शिवकुमार ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन पार्टी द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई।

इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की

नई दिल्ली। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई नेताओं ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोग के साथ बैठक की और विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। कांग्रेस, राजद, माकपा, भाकपा, भाकपा (माले), राकांपा (शरदचंद्र पवार) और समाजवादी पार्टी सहित 11 दलों के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य आयुक्तों से मुलाकात की। इन नेताओं ने आपत्ति जताई कि बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले मतदाता सूची की इस तरह की विशेष जांच कराना उचित नहीं है। यह प्रक्रिया पहले ही बिहार में शुरू हो चुकी है और अगले साल जिन पांच और राज्यों असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, वहां भी इसे लागू किया जाना है। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग के उस नए निर्देश का भी विरोध किया, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ पार्टी अध्यक्ष ही आयोग के दफ्तर में प्रवेश कर सकते हैं। सिंघवी ने कहा, पहली बार हमें चुनाव आयोग में प्रवेश के नियम बताए गए। पहली बार कहा

गया कि सिर्फ पार्टी अध्यक्ष ही आ सकते हैं। इस तरह की पाबंदी से आयोग और राजनीतिक दलों के बीच जरूरी संवाद नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि पहले से सूची देकर भी नई वरिष्ठ नेताओं को तीन घंटे तक बाहर

बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जताई आपत्ति

इंतजार करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में 2003 में आखिरी बार एसआईआर हुआ था, जो लोकसभा चुनाव से एक साल पहले और विधानसभा चुनाव से 24 महीने पहले हुआ था। जबकि अब तक बिहार में चार-पांच चुनाव हो चुके हैं। बिहार में कुल लगभग आठ करोड़ मतदाता हैं। राजद नेता मनोज झा ने पूछा कि क्या यह प्रक्रिया लोगों का वोटिंग अधिकार छीनने संकेत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत में छेड़छाड़ की गई, तो वह विरोध करेंगे। उन्होंने मतदाता सूची में बदलाव के लिए मांगे जा रहे दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए गए। भाकपा (माले) नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार की लगभग 20 फीसदी आबादी काम की तलाश में राज्य से बाहर जाती है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग कहता है कि आपको मूल निवासी होना होगा। तो क्या प्रवासी मजदूर बिहार के मतदाता नहीं हैं? गरीबों के पास ये प्रमाणपत्र नहीं होंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि उसने एसआईआर प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया है कि मतदाता सूची से अपात्र नाम हटाए जाएं और योग्य नागरिकों को शामिल किया जाए, जिससे वे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

साथ ही आयोग का कहना है कि अवैध प्रवासियों का मतदाता सूची में नाम न मिले, इसके लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

पंजाब में बाढ़ का खतरा, कंट्रोल रूम किए स्थापित

लुधियाना। मॉनसून सीजन के मद्देनजर किसी भी प्रकार के हालातों से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों के साथ मीटिंग कर जरूरी इंतजाम अमल में लाने के निर्देश देते हुए बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला कार्यालय समेत 8 सब-डिवीजनों में कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। ए.डी.सी. राकेश कुमार ने बताया कि इन कंट्रोल रूम से 24 घंटे जानकारी ली जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम, पशुपालन विभाग, नगर पालिकाओं की जरूरी प्रबंध मुकम्मल करने के साथ जरूरी दवाओं और मशीनरी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को शहर में पड़ते सतलुज दरिया के नाजुक स्थानों और बांधों की भी समीक्षा कर वहां जरूरी प्रबन्ध करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम के नंबर - 01612433100 पर 24 घंटे कॉल कर सकते हैं जहां उनकी सहूलियत के लिए स्टाफ तैनात रहेगा। इस अवसर पर उनके साथ आई.ए.एस. (अंडर ट्रेनी) प्रगति रानी, एस.डी.एम. डॉ. पूनमप्रीत कौर एस.डी.एम. खन्ना बलजिंदर सिंह ढिल्लों और सहायक कमिश्नर पायल गोयल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवीन पूनिया को भारतीय महिला हैंडबाल टीम का कोच बनने पर दी बधाई

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने श्री नवीन पूनिया को भारतीय महिला हैंडबाल टीम का कोच बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। नवीन पूनिया एक बहुप्रतिभा के धनी हैं। सेना में रहते हुए भी उन्होंने अपनी खेल प्रतिभा व हमारी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया है। आज यहां जारी एक बधाई संदेश में श्री नायब सिंह सैनी ने आशा व्यक्त की है कि नवीन पूनिया कोच के रूप में भारतीय महिला टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे और टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर प्रदेश व देश का नाम रोशन करेगी। नवीन पूनिया भारतीय हैंडबाल टीम के उपकप्तान भी रहे हैं और कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम को पदक जीतवाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नवीन पूनिया इससे पहले भी नशा मुक्त हरियाणा अभियान चलाने में अपने गानों के माध्यम से युवाओं को जागरूक कर चुके हैं।

पात्र लोगों को पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवाने में नहीं आनी चाहिए कोई दिक्कत : रणबीर गंगवा

चंडीगढ़ । प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र को लेकर आ रही समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को इस सम्बंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। राज्य के विभिन्न पिछड़ा वर्ग समुदायों के प्रतिनिधिमंडलों ने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई थी कि उनके बच्चों को पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (एनसीएल) बनवाने में सरल पोर्टल के माध्यम से तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ईसी की पार्टियों से अपील-

बेबुनियाद आरोपों से कुछ हासिल नहीं होगा

नई दिल्ली । बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस पहले ही कई पार्टियों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने पार्टियों से अपील करते हुए कहा कि इन बेबुनियाद आरोपों से कुछ हासिल नहीं होगा इसलिए समय गंवाने की जगह सभी दल मतदान केंद्र पर अपने बीएलए नियुक्त करें। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मांग पर विपक्षी दलों के साथ बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक को टाल दिया है। सूत्रों के अनुसार, बैठक इसलिए स्थगित की गई क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक अपनी उपस्थिति की पुष्टि नहीं की थी। सूत्रों ने अनुसार कांग्रेस ने 30 जून को चुनाव आयोग को एक ईमेल भेजा था। इस ईमेल में कांग्रेस ने बिहार की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से 2 जुलाई को चुनाव आयोग के साथ तत्काल बैठक की मांग की थी। इसी बीच तेजस्वी यादव ने आयोग पर वार किया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने आजतक हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए। चीफ इलेक्शन कमीशन सामने आकर बात क्यों नहीं करते।क्यों मिस्टर इंडिया बने हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को मिस्टर इंडिया नहीं बनना चाहिए।

51 लोगों की मौत, कई लापता... हिमाचल में कुदरत का कहर, सैलाब में बह गया सबकुछ; 500 करोड़ का नुकसान

धर्मशाला। इस समय मौसम हिमाचल में कहर बरपा रहा है। मंडी जिले में मंगलवार को बादल फटने से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। गोहर, करसोग, थुनाग व धर्मपुर उपमंडल में सात स्थानों पर बादल फटने से मकान जमींदोज होने व बाढ़ के पानी में बहने से 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 लोग लापता हैं। गोहर उपमंडल में पांच, सराज में चार व करसोग में एक व्यक्ति की मौत हुई है। ग्रामीणों व प्रशासन ने 132 लोगों को बचाया है। वहीं, नए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 51 लोगों की जान चली गई है और 22 अन्य लापता हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के तहत राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) ने 20 जून से 1 जुलाई तक की अवधि को कवर करते हुए 2 जुलाई को एक संचयी क्षति आकलन रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में राज्य के 12 जिलों में मानव जीवन, निजी संपत्तियों, पशुधन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए महत्वपूर्ण नुकसान का खुलासा किया गया है।

कई लोग लापता

एसईओसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब तक कई कारणों से कुल 51 मौतें हुई हैं, जिनमें अचानक बाढ़, डूबना, भूस्खलन, बिजली गिरना और सड़क दुर्घटनाएं शामिल हैं। वहीं, कई लोग लापता हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मानसून से संबंधित घटनाओं में 103 लोग घायल हुए हैं। संपत्ति और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान राज्य ने 204 घरों को नुकसान पहुंचने की सूचना दी है, जिनमें से 22 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में अभी तक 500 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। नुकसान और भी बढ़ सकता है। जहां पर नुकसान हुआ है वहां राहत और पुनर्वास में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार आपदा की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है और हर स्थिति से निपटने का हरसंभव प्रयास कर रही है। लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, बिजली आपूर्ति हो या सड़क सुविधा सुचारू हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है।

सोनिया-राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी ने अधिग्रहण में फर्जी लेन-देन का किया दावा

नई दिल्ली । नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल ईडी ने अदालत में दावा किया है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण में फर्जी लेन-देन किया गया। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ईडी की तरफ से अदालत में पेश हुए। एसवी राजू ने बताया कि यंग इंडियन नामक कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया। एजेएल की संपत्ति 2000 करोड़ रुपये है। एजेएल के अधिग्रहण के लिए ही यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को बनाया गया था। एसवी राजू ने बताया कि एजेएल के निदेशक ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया कि वे कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि अखबार का प्रकाशन बंद हो चुका है और उनके पास आय का कोई नियमित साधन नहीं है। एसवी राजू ने कहा कि यंग इंडियन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा प्रबंधकीय पदों पर थे। राजू ने कहा कि कंपनी एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपये की

संपत्ति है, जिसका 90 करोड़ रुपये के कर्ज के बदले अधिग्रहण कर लिया गया। यह एक धांधली है, जिसमें कोई असल लेन-देन नहीं हुआ। एजेएल का अधिग्रहण कांग्रेस ने नहीं किया बल्कि यंग इंडियन ने किया। यह एक साजिश के तहत किया गया। ईडी ने कहा कि कांग्रेस ने न तो ब्याज दिया और न ही जमानत और 90 करोड़ रुपये के कर्ज को सिर्फ 50 लाख रुपये में बेचा गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर यह साजिश रची गई। एसवी राजू ने कहा कि यंग इंडियन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76 प्रतिशत शेयर हैं। नेशनल हेराल्ड की स्थापना पूर्व पीएम पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1938 में की थी। इसे कांग्रेस का अखबार माना जाता था। साल 2008 में इसने कर्ज में फंसने के चलते काम बंद कर दिया।

कंपनी ने तेलंगाना फार्मा प्लांट विस्फोट में 40 मौतों की पुष्टि की, एक-एक करोड़ के मुआवजे का भी एलान

हैदराबाद । तेलंगाना के पशमलाराम में फार्मा प्लांट में हुए विस्फोट में सिगाची इंडस्ट्रीज ने 40 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। कंपनी ने मृतकों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने का एलान किया है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस दुख के साथ तेलंगाना कारखाने में हुई दुर्घटना की जानकारी साझा कर रहे हैं। इस हादसे में हमारी टीम के 40 सदस्यों की मौत हो गई और 33 से अधिक लोग घायल हो गए। कंपनी ने कहा कि दुर्घटना के बाद से ही हम आपातकालीन प्रतिक्रिया, परिवार सहायता का समन्वय कर रहे हैं। इसके अलावा जांच और अनुपालन प्रयासों में सहयोग दे रहे हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मृतकों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि घायलों को पूर्ण चिकित्सा और पुनर्वास सहायता मिलेगी। कंपनी ने कहा कि यह दुर्घटना प्लांट में रिएक्टर विस्फोट के कारण नहीं हुई। हम इसकी जांच के बाद सही जानकारी देंगे। तब तक प्लांट में 90 दिनों के लिए परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित रहेगा।

फैक्टरी प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा

विस्फोट पीड़ितों में से एक के परिवार के सदस्य की शिकायत के आधार पर संगारेड्डी पुलिस ने सोमवार को फैक्टरी प्रबंधन के खिलाफ धारा 105 (हत्या के बराबर नहीं) 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और बीएनएस की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

सीएम ने जताई थी नाराजगी

विस्फोट के बाद प्लांट के प्रबंध तंत्र सामने नहीं आने पर सीएम रेवंत रेड्डी ने फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कंपनी के प्रबंधन के साथ बातचीत करेगी। गंभीर रूप से घायल लोगों को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि जो लोग घायल हैं, लेकिन कुछ हद तक ठीक होने के बाद काम पर लौट सकते हैं, उन्हें पांच लाख रुपये दिए जाएंगे।

मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया, प्रति व्यक्ति कर्ज 4.8 लाख रुपए हुआ- जयराम रमेश

नई दिल्ली।कांग्रेस ने भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से संबंधित खबरों का हवाला देते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। पिछले दो साल में प्रति व्यक्ति कर्ज 90 हजार रुपए से बढ़कर 4.8 लाख रुपए हो गया है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि जनता कर्ज में डूब रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र मुनाफा कमा रहे हैं तथा उनकी संपत्ति बढ़ती ही जा रही है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, अच्छे दिन का कर्ज! मोदी सरकार ने पिछले ग्यारह सालों में देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई प्रयास नहीं किया गया, केवल पूंजीपति मित्रों के लिए सारी नीतियां बनाई गईं, जिसका अंजाम आज देश की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई किसी न

किसी तरह हर रोज हमारे सामने आ रही है। रमेश ने कुछ खबरों का हवाला देते हुए दावा किया, रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट से भारत की अर्थव्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। सरकार कि ओर से आंकड़ेबाजी और विशेषज्ञों का सहारा लेकर असली कमियों को छुपाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश पर कर्ज का बोझ मोदीराज में चरम पर है। उन्होंने कहा कि दो साल में प्रति व्यक्ति कर्ज 90,000 रुपए बढ़कर 4.8 लाख रुपए हो गया है यानी लोगों की आमदनी का 25.7 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया, सबसे ज्यादा 55 प्रति कर्ज तथाकथित रूप से क्रेडिट कार्ड, मोबाइल ईएमआई आदि के लिए जा रहा है, जिसका मतलब है इस महंगाई में परिवारों की आय में उनका गुजारा नहीं हो रहा है और वे कर्ज लेने पर मजबूर हैं। असुरक्षित कर्ज 25 प्रतिशत पार हो चुका है। रमेश के अनुसार, सबसे चिंताजनक बात यह है कि मार्च 2025 तक भारत पर दूसरे देशों का/बाहरी कर्ज 736.3 अरब डॉलर था, जो पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने दावा किया कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से जनता त्रस्त है और संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जनता कर्ज में डूब रही है और प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र मुनाफा कमा रहे हैं, उनकी संपत्ति बढ़ती ही जा रही है। रमेश ने कहा, सीधा सवाल यह है कि जब सारी सरकारी परियोजनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी या निजी भागीदारी से ही हो रहे हैं तो देश पर कर्जा क्यों बढ़ रहा है तथा हर देशवासी पर 4,80,000 रुपये का कर्ज क्यों हो गया है ?

अमेरिकी फेड सितंबर से पहले ब्याज दरों में कटौती फिर से शुरू नहीं कर सकता, बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट

नई दिल्ली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से सितंबर 2025 से पहले अपने सहजता चक्र (ब्याज दर घटाने के दौर) को फिर से शुरू करने की संभावना नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है। यह उम्मीद हाल में जारी जॉब ओपनिंग और लेबर टर्नओवर सर्वे के आधार पर जताई गई है। सर्वे में मई 2025 के दौरान उम्मीद से अधिक मजबूत जॉब ओपनिंग दिखी है। JOLTS डेटा से पता चला है कि मई 2025 में अमेरिका में जॉब ओपनिंग बढ़कर 7.76 मिलियन हो गई। यह अप्रैल 2025 में 7.39 मिलियन थी। हालांकि, हेल्थकेयर और बिजनेस सर्विसेज सेक्टर में बड़ी गिरावट के साथ हायरिंग घटकर 5.5 मिलियन रह गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मिश्रित श्रम बाजार डेटा के अनुसार नौकरी की उपलब्धता मजबूत बनी हुई है, लेकिन वास्तविक हायरिंग गतिविधि धीमी हो रही है। रिपोर्ट में यूएस फेडरल रिजर्व चेयर की टिप्पणियों पर भी प्रकाश डाला गया, जिन्होंने दोहराया कि फेड «प्रतीक्षा करो और देखो» मोड में रहना जारी रखेगा। केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर कोई भी निर्णय लेने से पहले हाल के टैरिफ उपायों के आर्थिक प्रभाव का सावधानीपूर्वक आकलन कर रहा है।

इस बीच, अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र में सुधार के कुछ संकेत दिखाई दिए। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जून में बढ़कर 49 हो गया, जो मई में 48.5 से छह महीने का उच्चतम स्तर है। सुधार के बावजूद, सूचकांक 50 अंक से नीचे बना हुआ है, जो निरंतर संकुचन को दर्शाता है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा के मूल्य सूचकांक घटक में परिलक्षित मुद्रास्फीति जोखिम बना हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निवेशकों से अब श्रम बाजार की प्रवृत्ति के बारे में अधिक जानकारी के लिए आगामी अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यूके के बारे में बताया गया है कि औसत आवास मूल्य वृद्धि मई में 3.5 प्रतिशत से जून में 2.1 प्रतिशत तक धीमी हो गई। यह नरमी कमजोर मांग को इंगित करती है, संभवतः स्टांप ड्यूटी में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के कारण। वैश्विक बॉन्ड बाजार के मोर्चे पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और चीन को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में पैदावार में गिरावट आई है। सीनेट की ओर से ट्रम्प प्रशासन के खर्च विधेयक को पारित करने के बाद यूएस 10-वर्षीय ट्रेजरी पैदावार में 1 आधार अंक की वृद्धि हुई। भारत में, वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट के बाद 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड पैदावार में 3 आधार अंकों की गिरावट आई। हालांकि, अब यह थोड़ा बढ़कर 6.30 प्रतिशत पर कारोबार कर रहा है, जो वैश्विक बांड बाजारों में हलचल का संकेत है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की इंक्रीमेंटल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 6.7 फीसदी, अकेले एसबीआई का योगदान 1.1फीसदी

नई दिल्ली। भारत ने वित्त वर्ष 25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धिशील वृद्धि में लगभग 6.7 प्रतिशत का योगदान दिया और अकेले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की वृद्धिशील वृद्धि में 1.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर भारत के मजबूत प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है, जिसने वित्त वर्ष 25 के दौरान वैश्विक जीडीपी में कुल वृद्धि में 297 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़े। इसमें कहा गया है, «वैश्विक स्तर पर, भारत ने वित्त वर्ष 25 में वृद्धिशील वैश्विक जीडीपी में लगभग 6.7 प्रतिशत का योगदान दिया। वित्त वर्ष 25 में विश्व अर्थव्यवस्था में 4,118 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई और इसमें भारत की हिस्सेदारी 297 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसका मतलब है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुल वृद्धि में भारत का योगदान लगभग 7 प्रतिशत था, जो वैश्विक विकास में अग्रणी योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में इसके बढ़ते महत्व और ताकत को दर्शाता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत के योगदान में से, अकेले एसबीआई ने अपनी संपत्ति के आकार के माध्यम से 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़े। एसबीआई का यह योगदान वित्त वर्ष 25 में वैश्विक जीडीपी में कुल वृद्धि का लगभग 1.1 प्रतिशत है। शोध रिपोर्ट में कहा गया है, एसबीआई वैश्विक जीडीपी में लगभग 1.1 प्रतिशत और भारत के जीडीपी में लगभग 16 प्रतिशत जोड़ता है।« दूसरे शब्दों में, अकेले एसबीआई का प्रदर्शन वैश्विक जीडीपी वृद्धि में कुछ छोटी अर्थव्यवस्थाओं के योगदान के आकार से मेल खाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीआई वित्त वर्ष 25 में भारत के कुल जीडीपी जोड़ में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है, जो देश के आर्थिक इंजन में बैंक की मजबूत भूमिका को दर्शाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एसबीआई ने वित्त वर्ष 25 के दौरान भारत में वित्तीय सेवाओं के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 8.7 प्रतिशत का योगदान दिया। बैंक का सकल मूल्य वर्धन वित्त वर्ष 25 में 1,38,533 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 24 में 1,32,157 करोड़ रुपये था। यह एसबीआई के मूल्य वर्धन में साल-दर-साल 5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

2025 की पहली छमाही में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री धीमी, मारुति-ह्युंडै जैसे ब्रांडों पर दिखा असर

बिजनेस डेस्क। वर्ष 2025 की पहली छमाही में भारत में घरेलू यात्री वाहनों की मांग कुछ धीमी रही है। देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनियों मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और ह्युंडै को इस दौरान बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा है। वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा और स्कोडा जैसी कंपनियों ने अपने नए मॉडल्स की बदौलत इस गिरावट के ट्रेंड से खुद को काफी हद तक बचा लिया।

ऑटोमोबाइल सेक्टर के शुरुआती अनुमान बताते हैं कि जून 2025 में थोक स्तर पर वाहन डिस्पैच 6.4 फीसदी घटकर करीब 3.2 लाख यूनिट्स पर आ गया, जबकि खुदरा बिक्री (रजिस्ट्रेशन) 4.4फीसदी गिरकर 2.94 लाख यूनिट रही। मारुति सुजुकी, जो देश की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता है, ने इस साल की पहली छमाही में 2.2फीसदी गिरावट के साथ 8.80 लाख से कुछ अधिक वाहनों की डिलीवरी की। अकेले जून महीने में कंपनी की डिस्पैच 13.3 फीसदी गिरकर 1.18 लाख यूनिट्स पर आ गई। खासतौर पर यूटिलिटी वाहन श्रेणी में भी गिरावट देखी गई, जो 52,373 से घटकर 47,947 रह गई। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल और ईवी यूनिट के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने कहा कि मई और जून में मांग में काफी सुस्ती रही, जिससे वॉल्यूम दबाव देखने को मिला। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रेणी में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जो नए मॉडलों की वजह से मुमकिन हो सका। ह्युंडै मोटर इंडिया ने भी साल की पहली छमाही में 7.7फीसदी की गिरावट दर्ज की और इस दौरान 2.85 लाख वाहन डिस्पैच किए। जून महीने में यह गिरावट और तेज रही, जब बिक्री 12फीसदी घटकर 44,024 यूनिट्स रह गई।

इसके विपरीत, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने 2025 की पहली छमाही में 3.01 लाख से ज्यादा वाहनों की बिक्री कर 20फीसदी की ग्रोथ दर्ज की। जून में बिक्री 18 फीसदी बढ़कर 47,306 यूनिट्स पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 40,022 थी। M&M की ग्रोथ में इसके इलेक्ट्रिक वाहनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्हें कंपनी ने मार्च से डीलर्स तक भेजना शुरू किया था। कुल मिलाकर, जबकि कुछ दिग्गज कंपनियों को बाजार की धीमी गति का असर झेलना पड़ा, वहीं इलेक्ट्रिक सेगमेंट और नए मॉडल पेश करने वाली कंपनियों ने इस मंदी में भी अपना ग्रोथ कायम रखा।

13 फीसदी प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुआ एचडीएफसी फाइनेंशियल, एचडीएफसी बैंक ने दिया लंबे समय तक समर्थन का भरोसा

नई दिल्ली। एचडीएफसी बैंक की सहायक कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर बुधवार को अपने निर्गम मूल्य 740 रुपये से लगभग 13 प्रतिशत प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुए। इश्यू प्राइस यानी निर्गम मूल्य, वह प्रारंभिक मूल्य है जिस पर कोई कंपनी अपने शेयर या बॉन्ड जनता को पहली बार जारी करती है। बीएसई पर कंपनी के शेयर की शुरुआत 835 रुपये पर हुई, जो निर्गम मूल्य से 12.83 प्रतिशत अधिक है। बाद में यह 14.29 प्रतिशत बढ़कर 845.75 रुपये पर पहुंच गया।

वहीं एनएसई में कंपनी के शेयर 835 रुपये पर सूचीबद्ध हुए। शुरुआती कारोबार के दौरान कंपनी का बाजार पूंजीकरण 69,658.72 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। संस्थागत खरीदारों की उत्साहजनक भागीदारी के बीच, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के 12,500 करोड़ रुपये के आरंभिक शेयर बिक्री को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। यह पिछले शुक्रवार को बोली के अंतिम दिन 16.69 गुना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ का प्राइस बैंड 700 से 740 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इसमें 2,500 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किए गए और 10,000 करोड़ रुपये की बिक्री प्रवर्तक एचडीएफसी बैंक द्वारा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत की गई।

कंपनी के नए निर्गम से प्राप्त राशि का उपयोग अपने टियर-1 पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए करेगी। इसमें अतिरिक्त उधार देना भी शामिल है, ताकि कारोबार की वृद्धि को सहारा मिल सके। एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ पिछले तीन वर्षों में दूसरा सबसे बड़ा निर्गम रहा, पहले स्थान पर दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई का 27,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव था। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन ने कहा कि बैंक अपनी सहायक कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को सूचीबद्धता के बाद भी समर्थन देना जारी रखेगा। उन्होंने 12,500 करोड़ रुपये के आईपीओ के बारे में कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है।

घरेलू शेयर बाजार में हरियाली बरकरार; सेंसेक्स ने पकड़ी रफ्तार, निफ्टी में भी लगाई छलांग

मुंबई। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को भी हरियाली बरकरार रही। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 236.56 अंक चढ़कर 83,933.85 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 66.3 अंक चढ़कर 25,608.10 पर पहुंचा। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 85.62 पर आ गया। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 90.83 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 83,697.29 पर बंद हुआ था। निफ्टी 24.75 अंक या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 25,541.80 पर बंद हुआ था। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में आईटी और ऑटो सेक्टर में खरीदारी देखी गई। सुबह सेंसेक्स 225.5 अंक या 0.27 फीसदी बढ़कर 83,922.79 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 58.75 अंक या 0.23 प्रतिशत बढ़कर 25,600.55 पर था। सेंसेक्स पैक में इंफोसिस, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस,

टाटा स्टील, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक और अडाणी पोर्ट्स टॉप गेनर्स रहे। एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, बीईएल और इटरनल टॉप लूजर्स रहे। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 1 जुलाई को अपनी बिकवाली जारी रखी और 1,970.14 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने अपनी खरीद जारी रखी और उसी दिन 771.08 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। एशियाई बाजारों में बैंकॉक, चीन, जापान, सोल और जकार्ता लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि केवल हांगकांग हरे निशान में कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में अमेरिका में डाउ जोंस 400.17 अंक या 0.91 प्रतिशत की बढ़त के साथ 44,494.94 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 इंडेक्स 6.90 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 6,198.05 पर बंद हुआ और नैस्डैक 166.85 अंक या 0.82 प्रतिशत की गिरावट के साथ 20,202.89 पर बंद हुआ था। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.06 प्रतिशत बढ़कर 67.15 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

महाराष्ट्र में ई-चालान के खिलाफ ट्रक चालक हड़ताल पर; ट्रांसपोर्टर संगठन ने कहा, मिलाजुला असर

नई दिल्ली।

महाराष्ट्र में ट्रक चालक ई-चालान प्रणाली के विरोध और अन्य लंबित मांगों को लेकर बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे से पूरे राज्य में माल परिवहन सेवाएं बाधित हुईं। ट्रांसपोर्टरों के प्रतिनिधियों ने यह जानकारी दी। ट्रांसपोर्टरों ने शिकायत की है कि अधिकारियों की वसूली प्रक्रिया आक्रामक हो गई है। इससे व्यापार संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है, साथ ही ई-चालान का जुर्माना बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टर संघों की एक कार्रवाई समिति, वाहतुकदार बचाओ कृति संगठन ने हड़ताल का आह्वान किया। ट्रक चालकों ने जहां मध्य रात्रि से हड़ताल शुरू कर दी, वहीं बस संचालकों ने अगले कुछ दिनों के लिए हड़ताल में भाग लेने को स्थगित कर दिया है। एक्शन कमेटी के संयोजक उदय बर्गे ने दावा किया, हड़ताल का यह पहला दिन है, इसलिए इसे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन दोपहर बाद स्थिति अलग होगी। उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारण मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में 1.5 लाख और 2 लाख ट्रक और अन्य मालवाहक वाहन सड़कों से नदारद रहेंगे। बर्गे ने दावा किया कि मुंबई के व्यापारिक केंद्र कालबादेवी में सभी ट्रक सड़कों से नदारद हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में परिवहन संघों के सदस्य ट्रांसपोर्टरों को हड़ताल में

शामिल होने के लिए राजी करने के लिए गांधीगिरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों की मांगों में ई-चालान जुर्माना की जबरन वसूली बंद करना, छह महीने से पुराने ई-चालान रद्द करना, मौजूदा जुर्माने को माफ करना, भारी वाहनों के लिए अनिवार्य क्लीनर नियम को खत्म करना और मेट्रो शहरों में नो-एंट्री समय पर पुनर्विचार करना शामिल है। हड़ताल के आह्वान को देखते हुए राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए मुंबई यातायात पुलिस, राजमार्ग पुलिस और मोटर वाहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ परिवहन संघों के नेताओं की एक 10 सदस्यीय समिति गठित की है। मंगलवार देर रात जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 26 जून को ट्रांसपोर्टरों की मांगों पर विचार करने के लिए समिति के गठन का आश्वासन दिया। ट्रांसपोर्टरों ने अपनी मांगों को लेकर 16 जून से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उद्योग मंत्री उदय सामंत द्वारा उनके मुद्दों को हल करने के लिए बैठक बुलाने का आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने 24 जून को अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। अगले दिन हुई बैठक में सरनाईक और सामंत ने मांगों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया। हालांकि, ट्रांसपोर्टर छह महीने से पुराने ई-चालान वापस लेने के संबंध में राहत न मिलने का हवाला देते हुए जुलाई में हड़ताल के अपने फैसले पर अड़े रहे।

एक नजर

गलत तरीके से ट्रायल करने के आरोपों पर एचसीजी की सफाई, कहा- परीक्षण में रोगी सुरक्षा पर देते हैं ध्यान

बंगलूरू। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एचसीजी) ने प्लांट में गलत तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं के गलत तरीके से क्लीनिकल ट्रायल करने के आरोपों पर सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि हम अपनी एथिक्स कमेटी के अनुमोदन के आधार पर ट्रायल करते हैं। इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाती है और रोगी सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता है। हाल ही में एचसीजी पर कंपनी की एथिक्स कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति पी कृष्ण भट ने गलत तरीके से ट्रायल करने आरोप लगाए थे। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) को पत्र लिखकर एचसीजी में होने वाले क्लीनिकल ट्रायल्स की जांच की मांग की थी। इसके जवाब में एचसीजी ने कहा कि वह डीसीजीआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) सहित नियामक प्राधिकरणों के निर्देशों का सख्ती से पालन करती है। कंपनी ने कहा कि हमने भारत और अफ्रीका में कैंसर देखभाल में कंपनी के बारे में कुछ असत्यापित जानकारी देखी है। हम आश्वस्त करते हैं कि हम डीसीजीआई और आईसीएमआर सहित नियामक प्राधिकरणों के निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं। एचसीजी के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. बीएस अजय कुमार ने कहा कि हम अपनी एथिक्स कमेटी द्वारा अनुमोदित रोगी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, अत्यंत पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक बड़ी संख्या में ट्रायल कर रहे हैं। असाधारण देखभाल प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता अटल है। एचसीजी भारत में एक अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है जो कैंसर देखभाल, तृतीयक देखभाल, बांझपन उपचार और उन्नत जांच और क्लीनिकल सेवाएं प्रदान करता है। इसकी चार संस्थाएं हैं- एचसीजी- कैंसर देखभाल में विशेषज्ञ, एचसीजी हॉस्पिटल-मल्टीस्पेशलिटी केयर के लिए, मिलन- प्रजनन केंद्र, और ट्रिएस्टा साइंसेज - डायग्नोस्टिक सेंटर। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा के आयुक्त शिवकुमार केबी ने कंपनी के खिलाफ जांच की मांग करते हुए डीसीजीआई को लिखे पत्र में कहा कि विभिन्न क्लीनिकल ट्रायल के संचालन के संबंध में एचसीजी में मरीजों की सुरक्षा, नियामक अनुपालन और संस्थागत अखंडता पर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। इसमें अनियंत्रित हितों का टकराव और मरीज नामांकन भी शामिल है। इन चिंताओं को किसी और ने नहीं, बल्कि संस्थागत एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष ने उठाया है, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया है।

वेतन विवाद पर इंडियन ऑयल की बॉटलिंग प्लांट में प्रदर्शन, विपक्ष का तृणमूल पर सिंडिकेट राज का आरोप

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बजबज स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में वेतन संबंधी विवाद विरोध में बदल गया है। दरअसल, एलपीजी ट्रांसपोर्टरों और उनके ड्राइवरों के बीच वेतन को लेकर विवाद चल रहा था। विरोध प्रदर्शन मंगलवार की रात को शुरू हुआ। इसके कारण अस्थायी रूप से उत्पादन बाधित हुआ। साथ ही इसे लेकर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया। बीजेपी नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना से संबंधित एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना तृणमूल कांग्रेस के शासन में तहत बढ़ती अराजकता और सिंडिकेट राज को दर्शाती है। इसके अलावा उन्होंने दो वीडियो भी साझा किए, जिनमें प्रदर्शनकारियों को सिलेंडरों से एलपीजी छोड़ते हुए दिखाया गया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। अधिकारी ने वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि कल का विरोध प्रदर्शन, जिसमें गुस्साए श्रमिकों ने सिलेंडरों से गैस सड़कों पर छोड़ी थी, भयावह हो सकता था। अगर एक चिंगारी भी लग जाती तो बजबज बॉटलिंग प्लांट के नजदीक बीबीआईटी कॉलेज, जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज और आसपास के इलाकों में भारी तबाही हो सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के आपसी गुट लोडिंग और अनलोडिंग के ठेकों को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं, जिससे कामगारों की जान खतरे में पड़ रही है। अधिकारी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता देबांग्शु भट्टाचार्य ने कहा कि यह एक औद्योगिक विवाद था और पुलिस ने समय पर कार्रवाई की। सुवेंदु अधिकारी को अपने अतीत में झांकना चाहिए। वह खुद भी सिंडिकेट चलाते थे और अब भी चलाते हैं। इंडियन ऑयल के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह विवाद वेतन को लेकर ट्रांसपोर्टर्स और उनके ड्राइवरों के बीच था। कंपनी का इससे कोई सीधा लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि अशांति के कारण शनिवार से ही उत्पादन और डिस्पैच पर असर पड़ा था। हालांकि वैकल्पिक स्रोतों से सिलेंडर आपूर्ति जारी रखी गई। अब बजबज प्लांट में उत्पादन दोबारा शुरू हो गया है। बजबज सुविधा आमतौर पर प्रतिदिन करीब 45,000 से 50,000 सिलेंडर भरती है। यह कोलकाता की एलपीजी मांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा करती है।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दो स्वतंत्र निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की

नई दिल्ली। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में दो स्वतंत्र निदेशकों और कई वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया है। बैंक ने बुधवार को बताया कि स्वतंत्र निदेशकों में एक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी और साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी जोखिम और नियामक प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ नंदकुमार सरवडे और दूसरे मानव पूंजी रणनीति में तीन दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले जगजीत मंगल प्रसाद हैं। इसके अलावा, बैंक ने योगेश जैन को मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), विवेक त्रिपाठी को मुख्य ऋण अधिकारी (सीसीओ) और धवन शाह को प्रमुख (वाणिज्यिक बैंकिंग) नियुक्त किया है। बैंक ने बयान में कहा कि अविनाश शरण को प्रमुख (शाखा बैंकिंग) और अरविंद बुटोला को राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख (क्रेडिट कार्ड और असुरक्षित ऋण) के पद पर पदोन्नत किया गया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक, प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संजय अग्रवाल ने कहा, «नई नियुक्तियां और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्नत भूमिकाओं में कदम रखना, अधिक विविधतापूर्ण भारत की सेवा करने, स्थिरता के साथ पैमाने का प्रबंधन करने और 'सच्चाई', 'ईमानदारी और 'जिम्मेदारी के माध्यम से स्थायी मूल्य बनाने की हमारी तत्परता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों के साथ बैंक, मुंबई को सभी व्यावसायिक परिचालनों के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में विकसित करना जारी रखेगा।

जून में घटी यूपीआई ट्रांजेक्शन की रफ्तार, मई के रिकॉर्ड के मुकाबले 1.5 फीसदी गिरावट

नई दिल्ली। भारत के डिजिटल भुगतान सिस्टम की रीढ़ माने जाने वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में जून 2025 में मामूली गिरावट देखने को मिली है। मई में रिकॉर्ड 18.68 अरब ट्रांजैक्शंस के बाद जून में यह संख्या घटकर 18.4 अरब रह गई, जो कि 1.5 प्रतिशत की गिरावट है। ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करें तो जून में कुल ₹24.04 लाख करोड़ का लेन-देन हुआ, जबकि मई में यह आंकड़ा 25.14 लाख करोड़ था यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू में भी 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, साल-दर-साल तुलना करें तो जून 2024 की तुलना में जून 2025 में UPI ट्रांजैक्शन की संख्या में 32 प्रतिशत और ट्रांजैक्शन वैल्यू में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जून में औसतन हर दिन 613 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जो मई के 602 मिलियन की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। हालांकि, प्रति दिन की वैल्यू 80,131 करोड़ रही, जो मई के 81,106 करोड़ से कम है। IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस में भी गिरावट देखने को मिली। मई में जहां 464 मिलियन लेनदेन हुए थे, जून में यह घटकर 448 मिलियन रह गए। ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 76.41 लाख करोड़ से घटकर 76.06 लाख करोड़ पर आ गई। इसी तरह, डिजिटल टोल भुगतान प्रणाली FASTag में भी जून में कमी आई है।

कुल 386 मिलियन ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए, जबकि मई में यह आंकड़ा 404 मिलियन था। ट्रांजैक्शन की वैल्यू भी 7,087 करोड़ से घटकर 6,793 करोड़ रह गई। Aadhaar Enabled Payment System (AePS) के जरिए भी ट्रांजैक्शन में गिरावट देखी गई। जून में कुल 97 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जो मई के 105 मिलियन से 8 प्रतिशत कम हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹26,616 करोड़ रही, जो पिछले महीने के 28,703 करोड़ की तुलना में 7 प्रतिशत कम है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट सीजनल यानी मौसमी हो सकती है और इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।